

कमला हैरिस ने ट्रम्प पर चार पाइन्ट्स की लीड स्थापित की

रॉयटर द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार, राष्ट्रपति पद पर 45 प्रतिशत लोग कमला हैरिस को देखना चाहते हैं तथा 41 प्रतिशत ट्रम्प को

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 अगस्त। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर बढ़त ले ली है। यह जानकारी मिली रॉयटर्स/इप्सॉस पोल के सप्ताहांत में नतीजों से। नतीजों के अनुसार, कमला को 45 प्रतिशत डॉनल्ड ट्रम्प को 41 प्रतिशत वोट मिले हैं। आठ दिन चला यह सर्वे शुरूवार को ही खत्म हुआ है। इसके अनुसार, जुलाई के अंत में हैरिस को मिली एक पाइन्ट की बढ़त के मुकाबले यह उल्लेखनीय बढ़त है। हैरिस को जो बढ़त मिल रही है उसके लिए महिलाओं और हिस्पैनिक मतदाताओं का बढ़ता समर्थन है। इन दोनों समूहों में उनकी लोकप्रियता ट्रम्प से 13 प्रतिशत अधिक है। दोनों समूहों में उनकी लोकप्रियता 49 से 36 प्रतिशत है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महिलाओं में उनकी लोकप्रियता 9 प्रतिशत तक और हिस्पैनिक मतदाताओं

- जुलाई के अन्त में कराये गये सर्वे में, कमला हैरिस की "लीड" केवल एक प्रतिशत थी।
- हैरिस की लीड में इतनी भारी बढ़ोतरी होने का कारण है, कमला हैरिस की लोकप्रियता में महिलाओं और हिस्पैनिक लोगों का समर्थन 13 प्रतिशत बढ़ा है, गत महीने के सर्वे रिज़ल्ट की तुलना में।
- इस सर्वे में अमेरिका के 4253 नागरिकों से तथा चुनाव में वोट देने के लिये रजिस्टर्ड 3562 अमेरिकी नागरिकों से यह सवाल पूछकर कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोट किसको देंगे, उनकी राय जानी थी।

में 6 प्रतिशत तक बढ़ी है, हालांकि श्वेत मतदाताओं और पुरुषों में ट्रम्प अभी भी आगे हैं, पर कॉलेज डिग्री रहित युवाओं में उनकी लोकप्रियता 7 पाइन्ट घटी है। जो बाइडन के राष्ट्रपति पद की चुनावी दौड़ से बाहर होने के बाद से हालात में काफी परिवर्तन आया है। बाइडन के पीछे हटने के बाद हैरिस को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रमुख राज्यों के

चुनावों में काफी बढ़त मिली है। विस्कॉन्सिन, पैन्सिलवेनिया, जॉर्जिया, एरिज़ोना, नॉर्थ कैरोलाइना, मिशिगन और नेवाडा जैसे राज्यों में जहाँ कड़ा मुकाबला है वहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स में ट्रम्प को हैरिस पर मामूली सी बढ़त प्राप्त है। लेकिन ब्लूमबर्ग न्यूज़/मॉनिंग कंसल्ट पोल से पता चलता है कि यहां पर तो हैरिस आगे चल रही है या ट्रम्प

के बराबर हैं। रिपब्लिकन नीतिकार मैट वॉल्किंग ने माना कि हैरिस से ट्रम्प को कड़ी चुनौती मिल रही है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प के लिए महत्वपूर्ण है कि वोटर्स का समर्थन बनाए रखने के लिए व चुनाव प्रचार रणनीति पर फोकस करें। जब से हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है तब से वे जॉर्जिया जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में सक्रिय चुनाव अभियान चला रही है ताकि उनका जनाधार मजबूत हो जाए। हैरिस के लिए जनता में उत्साह साफ नजर आ रहा है। रॉयटर्स/इप्सॉस सर्वे में शामिल 73 प्रतिशत डेमोक्रेटिक वोटर्स ने कहा कि नवम्बर में होने वाली वोटिंग के प्रति उनका उत्साह बढ़ गया है। प्रगतिवादी सोच के मतदाताओं में ट्रम्प की तुलना में हैरिस का असर ज्यादा है। हैरिस के 52 प्रतिशत मतदाताओं ने कहा कि उनका लक्ष्य ट्रम्प का विरोध करने से कहीं ज्यादा हैरिस को मजबूत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

8 सितम्बर को 3 दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी

विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 अगस्त। विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले विदेश दौरे में राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। वे 8 से 10 सितम्बर तक अमेरिका में रहेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने कहा कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं तब से उनके पास बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी से मिलने का आग्रह किया गया है। गांधी 8 सितम्बर को डलास, टेक्सास में रहेंगे तथा 9 व 10 सितम्बर को वाशिंगटन डी.सी. में रहेंगे। इस दौरान वे शिक्षाविदों, पत्रकारों, थिंक टैंक्स के प्रतिनिधियों टेक्नोक्रेट्स, व्यवसायियों व भारतीय मूल के अन्य लोगों व स्थानीय लोगों से मिलेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जिसकी उपस्थिति 32 देशों में है, के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल की यात्रा की औपचारिक घोषणा करते हुए बताया कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता

- इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि जब से राहुल विपक्ष के नेता बने हैं, उनसे मिलने के लिए हमारे पास अनगिनत आवेदन आए हैं।
- पित्रोदा ने कहा कि तीन दिन के प्रवास में राहुल गांधी शिक्षाविदों, पत्रकारों, उद्योगपतियों, भारतीय मूल के लोगों व छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे तथा विभिन्न मसलों पर चर्चा करेंगे।

बने हैं, मेरे पास भारतीय मूल के लोगों, इंटरनैशनल मीडिया व अन्य नेताओं की तरफ से आवेदनों की भरमार लगी है। वे सभी राहुल से बात करना चाहते हैं। अब राहुल संक्षिप्त दौरे पर अमेरिका आ रहे हैं। डलास में गांधी युनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों, शिक्षाविदों व अन्य लोगों से वार्ता करेंगे। कुछ टेक्नाफ्रेस्ट से भी चर्चा होगी और रात्रि भोज पर डलास के नेताओं से मिलेंगे। वाशिंगटन में वे थिंक टैंक और

नैशनल प्रेस क्लब व अन्य लोगों से मिलेंगे। पित्रोदा ने बताया कि कई लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। लोगों को उन राज्यों में भी काफी रूचि है जहाँ कांग्रेस का शासन है। खासकर बैंगलुरु, हैदराबाद और उम्मीद है कि हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे क्योंकि लोगों को पुणे, मुंबई व गुडगांव में भी दिलचस्पी है। ये देश के बिज़नेस शहर हैं जहाँ टेक्नॉलजी पर काफी फोकस है। पित्रोदा ने कहा कि हम राहुल गांधी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यू.डी.एच. सचिव और डी.एल.बी. निदेशक को अवमानना नोटिस

जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने डिप्टी टाउन प्लानर के निलंबन से जुड़े मामले में करीब एक साल पुराने अदालती आदेश की पालन नहीं करने पर प्रमुख यू.डी.एच. सचिव टी.रविकान्त व डी.एल.बी. निदेशक सुरेश ओला को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह आदेश राजपाल चौधरी की अवमानना

- हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है।

याचिका पर दिया। याचिका में अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि याचिकाकर्ता डी.एल.बी. में डिप्टी टाउन प्लानर के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उन्हें बिना नाम व पते वाली झुठी शिकायत पर 13 फरवरी 2023 को चार्जशीट देते हुए निलंबित कर दिया। चार्जशीट भी उस अफसर ने दी जिसे देने का अधिकार नहीं था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साइबर फ्रॉड केस में पुलिस को अल्टीमेटम

जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर फ्रॉड के ढाई साल पुराने मामले में कार्रवाई नहीं होने और इन केसों में हो रही बढोतरी को गंभीर माना है। अदालत ने मौखिक रूप से राज्य सरकार को कहा कि जब सी.जे.आई. के साथ ही साइबर फ्रॉड हो चुका है तो फिर पुलिस ऐसे मामलों में इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है।

- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, सी.जे.आई. तक के साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है फिर भी पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है। कोर्ट ने 60 लाख रूपए के साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस को 30 दिन में कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया।

अदालत ने पुलिस को कहा है कि यदि 30 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 30 सितंबर को डी.जी.पी. व्यक्तिगत तौर पर अदालत में हाजिर होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण दें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश 60 लाख रूपए के साइबर फ्रॉड के मामले में राकेश तोतुका की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि मामला वर्ष 2022 से चल रहा है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी के स्वघोषित हनुमान संकट में हैं बिहार में?

क्या भाजपा, अपने एन.डी.ए. गठबंधन के साथी चिराग पासवान के पर कुतरना चाहती है?

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वघोषित हनुमान संकट में दिखाई दे रहे हैं।

राकेश कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति, जो उड़ती खबरों के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता हैं, ने एक याचिका लगाई है तथा चुनाव आयोग में भी शिकायत की है। उन्होंने तीन गंभीर आरोप लगाये हैं- पहली, वे (चिराग) एक दुष्कर्म केस में द्वितीय आरोपी हैं, दूसरी, उन्होंने अपने चुनाव-शपथपत्र में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के बारे में झूठ बोला था; तथा तीसरी, उन्होंने बिहार के खगड़िया जिले की अपनी सम्पत्ति के स्वामित्व को बात छुपाई थी। बिहार भाजपा के मोडिया प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण देते हुये कहा है कि याचिकाकर्ता का भाजपा से कोई सम्बंध नहीं है। लेकिन चिराग की पार्टी और भाजपा के बीच पैदा हो रहे इस संकट का परिदृश्य काफी बड़ा दिखाई दे रहा है।

एन.डी.ए. के सभी घटक दलों में, चिराग केन्द्र सरकार के हाल ही के नीतिगत निर्णयों के सर्वाधिक मुखर विरोधी रहे हैं। इन नीतियों में, वक्फ बिल में प्रस्तावित संशोधन, तथा नौकरशाही में सीधी एवं खींचक भर्त्स

- भाजपा के एक तथाकथित कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करायी है कि चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने से पहले जो शपथ पत्र के माध्यम से जानकारीयों प्रस्तुत की हैं, झूठ हैं, असत्य हैं।
- साथ ही भाजपा विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया कि चिराग पासवान की पार्टी के पाँच निर्वाचित सांसदों में से तीन "जॉइन्" करने को तैयार हैं।
- इस घटनाक्रम के बीच चिराग पासवान के मुख्य प्रतिद्वंदी तथा चिराग के चाचा पशुपति नाथ पारस अचानक सक्रिय हुए और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मिले तथा शाह को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।
- क्या ये संकेत है कि भाजपा खुश नहीं कि चिराग पासवान एन.डी.ए. के खिलाफ सबसे अधिक बोलने वाले नेता के रूप उभर रहे हैं। अतः उन्हें जमीन पर उतारना जरूरी है।

करने की योजना, जो अब वापस ले ली गई है, प्रमुख रूप से शामिल हैं। चिराग विपक्ष द्वारा की जा रही जातिगत जगनाण की मॉर्ग के समर्थन में भी आ गये थे। इन सभी मुद्दों पर सरकार द्वारा अपने कदम पीछे हटा लेने के साथ ही, भाजपा में एक सोच यह भी बनी है कि चिराग अपने कद से कुछ ज्यादा ही

बाहर निकल रहे हैं तथा उन्हें रोकने की जरूरत है। हाल ही के दिनों में, बिहार के एन.डी.ए. पार्टनरों में बड़ी तेजी से कुछ हलचल होती दिखाई दी है। चिराग के चाचा तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस गुमानमी से एकाएक ही (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तिथि एक अक्टूबर से बदलकर 5 अक्टूबर की

कांग्रेस और आप का कहना है, यह संकेत है कि हरियाणा में भाजपा हतोत्साहित है और अभी से अपनी गलती स्वीकार कर रही है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 31 अगस्त। भाजपा की इच्छा की सुस्पष्ट अनुपालना में, भारत के चुनाव आयोग ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतदान-तिथि 1 अक्टूबर से खिसका कर 5 अक्टूबर कर दी। जम्मू-कश्मीर के तृतीय चरण की मतदान तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वह 1 अक्टूबर ही बनी हुई है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित होंगे।

चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना में कहा, "चुनाव तिथि निर्धारण के बाद, राष्ट्रीय राजनैतिक दलों, प्रांतीय राजनैतिक दलों, तथा अखिल भारतीय विश्वनौद महासभा के आग्रह-पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें कहा गया था कि सदियों पुराने असोज अमावस्या त्योहार पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिये विश्वनौद समुदाय के लोग बहुत बड़ी

- चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का कारण है कि, ऑल इंडिया विश्वनौद महासभा का ज्ञापन मिला था कि सदियों पुराने त्योहार असोज अमावस्या पर हरियाणा के विश्वनौद राजस्थान जाते हैं, ऐसे में उनका वोट डालना संभव नहीं हो पाएगा।
- चुनाव आयोग ने एक और कारण यह बताया कि, सप्ताहांत के साथ कई छुट्टियाँ होने के कारण लोग प्रायः घूमने निकल जाते हैं।
- चुनाव आयोग ने कहा, इन कारणों से मतदान प्रतिशत में भारी कमी आ जाती इसलिए हरियाणा के चुनाव आगे सरकाए गए हैं।

संख्या में हरियाणा से राजस्थान जायेंगे। ई.सी. की अधिसूचना में कहा गया है, "पूर्व निर्धारित तिथि पर मतदान होने से बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते तथा हरियाणा विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती।"

24 अगस्त को हरियाणा भाजपा की 'राज्य चुनाव प्रबन्धन समिति' के सदस्य वरिन्डर गर्ग ने कहा था, "हमने यह तर्क दिया है कि विधानसभा चुनाव की तिथि 1 अक्टूबर (मंगलवार) के पहले सप्ताहान्त अवकाश तथा बाद में भी छुट्टियाँ हैं, जिससे मतदान-प्रतिशतता प्रभावित हो सकती है क्योंकि

लोग लम्बे सप्ताहान्त अवकाशों पर प्रायः छुट्टियाँ ले लेते हैं।" विपक्षी कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी ने इस कार्यवाही की आलोचना की है। पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता भूपिन्डर सिंह हुडा ने भाजपा पर प्रहार करते हुये कहा है कि पार्टी का रुख बताता है कि उसने पराजय पहले ही स्वीकार कर ली है। मोडिया ने इस वरिष्ठ नेता को यह कहते हुये उधुत्त किया है, "मतदान ई.सी. द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही होने चाहिये।....हरियाणा की जनता भाजपा सरकार को एक दिन भी सत्ता में देkhना नहीं चाहती।" आप की हरियाणा इकाई ने कहा कि चुनाव होने से पहले ही, सत्तारूढ़ भाजपा ने बहाने तलाश करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसने चुनाव में आसन्न पराजय भोप ली है। जहाँ भाजपा हरियाणा में लगातार तीसरे कार्यकाल पर नज़रें जमाये हुये हैं, वहीं कांग्रेस सत्तारूढ़ दल को सत्ता सहेटा देने की आशा संजोये हुये है।

चेन्नई के हॉस्टल में रेड, 32 छात्र हिरासत में

चेन्नई, 31 अगस्त। तमिलनाडु में पुलिस ने शनिवार को उन हॉस्टलस में छापेमारी की, जहाँ चेन्नई के पास पोथेरी में प्राइवेट कॉलेज के छात्र रहते हैं। इस दौरान एक महिला समेत 32 कॉलेज स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। इन्हें

- पुलिस ने हॉस्टल में अचानक रेड डालकर छात्रों के कमरों से भारी मात्रा में गांजा, भांग का तेल व नशीली ड्रग्स इत्यादि बरामद की है।

एक निजी मैरिज हॉल में रखा गया है और अलग-अलग से पुछताछ की जा रही है। तांभर नगर पुलिस स्टेशन के कांस्टेबलों ने आज यह रेड मारी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। साथ ही भांग चॉकलेट, भांग का तेल और भांग से संबंधित दूसरी चीजें जब्त की गईं। पुलिस की ओर से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति में कानूनी मायाजाल में फंसी सरकार'

अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर हुई इस नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से और जल्दबाजी में यह नियुक्ति की

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में 2019 में नामांकित अधिवक्ता, पद्मेश मिश्रा, को राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पैरवी के लिये अतिरिक्त महाधिवक्ता (ए.ए.जी.) घोषित किये जाने के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता-अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने याचिका में मुख्य तौर पर इस मुद्दे पर जोर दिया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 की वाद नीति में संशोधन किया और एक नया 'क्लॉज 14.8' को जोड़कर स्वयं को बेलगाम शक्तियां देने का प्रावधान जोड़ा जिसके

तहत वे किसी भी अधिवक्ता, के अनुभव को आंकने के बाद, उसे अतिरिक्त महाधिवक्ता, महाधिवक्ता या किसी भी सरकारी वकील के पद पर नियुक्ति कर सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018 की वाद नीति में कोई और संशोधन नहीं किया जबकि इसी वाद नीति में 'क्लॉज 14.4' के अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिये अधिवक्ता के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिये। याचिकाकर्ता समदड़िया ने इस मामले में आवेदन दायर कर यह भी गृहण की थी कि पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति के आदेश पर तुरंत प्रभाव से

- याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि "राज्य सरकार ने वर्ष 2018 की वाद नीति में संशोधन किया और एक नया "क्लॉज 14.8" जोड़ा और स्वयं को बेलगाम शक्तियां दीं ताकि वो किसी भी अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति दे सके।
- परंतु उसने इसी वाद नीति के 'क्लॉज 14.4' में संशोधन नहीं किया, जिसके अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिये अधिवक्ता के पास कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिये।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता को नियुक्त करने से पूर्व राज्य के अधिवक्ता से ही सलाह नहीं ली गई थी, जो कि वाद नीति के 'क्लॉज 14.2' के अनुसार अनिवार्य है।

अंतिम रोक भी लगाई जाये। इस मामले की पहली सुनवाई करते हुए न्यायाधीश

अनिल उपमन ने राज्य सरकार तथा अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को नोटिस

जारी किये और कहा कि याचिकाकर्ता अगली सुनवाई पर नियुक्ति के आदेश

शेष अंतिम पृष्ठ पर)